



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2009/वैशाख 21, 1931

No. 269]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2009/VAISAKHA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2009

सं. 46/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 313(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, चीन जनवादी गणराज्य (चाइना पी. आर.) और चाइनीस ताईपेई (ताइवान) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित प्लास्टिक नेत्र लेंस, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 55/2004-सीमाशुल्क, तारीख 19 अप्रैल, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 268(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/18/2008-डीजीएडी, तारीख 22 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 22 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी;

और अभिहित प्राधिकारी ने समीक्षा के सम्पन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की थी;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी ने पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 103/2008-सीमाशुल्क, तारीख 4 सितम्बर 2008, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 642(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, के द्वारा संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क की अवधि 4 सितम्बर, 2009 तक बढ़ा दी थी;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी ने, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 15/18/2008-डीजीएडी, तारीख 12 फरवरी, 2009 जो कि भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 13 फरवरी, 2009 में प्रकाशित हुई थी के द्वारा अधिसूचना सं. 15/18/2008-डीजीएडी, तारीख 22 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रारंभ की गई जांच को रद्द कर दिया है और प्रतिपाटन शुल्क को आगे न बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) और उक्त नियम के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 55/2004-सीमाशुल्क, तारीख 19 अप्रैल, 2004 [सा. का.नि. 268 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2004] को उसके विखण्डन से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों की बाबत के सिवाय, विखण्डित करती है।

[फा. सं.-354/94/2003-टीआरयू(पार्ट-II)]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2009

No. 46/2009-Customs

G.S.R. 313(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/18/2008-DGAD, dated the 22nd August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1, dated the 22nd August, 2008, had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on plastic Ophthalmic lenses, (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from, the People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2004-Customs dated the 19th April, 2004 [G.S.R. 268(E), dated the 19th April, 2004];

And whereas the designated authority had requested for extension of anti-dumping duty, for a period of one year pending the completion of the review;

And whereas, on the basis of the aforesaid request of the designated authority, the Central Government had extended anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 103/2008-Customs, dated the 4th September, 2008, [published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 642(E), of same date up to 4th September, 2009;

And whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/18/2008-DGAD, dated the 12th February, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th February, 2009, had terminated the investigation initiated *vide* notification No. 15/18/2008-DGAD, dated the 22nd August, 2008 and recommended that the anti-dumping duties need not be extended further;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rule 14 of the said rules, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2004-Customs, dated the 19th April, 2004, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 19th April, 2004], except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/94/2003-TRU (Pt. II)]

UNMESH WAGH, Under Secy.